(b) Yes, Sir. A complaint has been received from Shri V. Hanumantha Rao, M.P.

(c) The complaint has been referred to the Government of Andhra Pradesh for a report.

(d) The question of issue of guidelines will be considered on receipt of information and report from the Government of Andhra Pradesh.

Posting of Officers in Tribal Areas

1798. SHRI MENTAY PADMANABHAM: Will the Minister of WELFARE be pleased to state :

(a) to what extent the Government of Andhra Pradesh has fulfilled its assurance of posting full time officers at Mandal level in all the tribal areas ; and

(b) the details of steps taken in this regard in Andhra Pradesh ?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI) : (a) and (b) Information is being collected from Government of Andhra Pradesh and it will be laid on the Table as soon as it is received.

सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुनर्वास

1799. **श्री राम सिंह राठवा :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों की मुक्ति और पुनर्वास के सम्बन्ध में घोषित योजनाएं असफल सिद्ध हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य वार निर्धारित लक्ष्य क्या थे तथा उनकी प्राप्ति कहां तक हो पायी है ;

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान इस उद्देश्य हेतु राज्य वार कितनी धनराशि दी गई है और इस में कितनी राशि आबंटित की गई है ;

(घ) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों ने इस सम्बन्ध में सहयोग नहीं दिया है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ङ) सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुनर्वास की योजना वित्तीय वर्ष 1991-92 के अंत में आरम्भ की गई थी । प्रत्येक वैयक्तिक सफाई कर्मचारी की पहचान के लिए प्रारम्भिक सर्वेक्षण का काम 12 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात आन्ध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर तथा संघ क्षेत्र राज्य पॉडिचेरी, में पूरा किया जा चुका है । अन्य राज्यों में अभी सर्वेक्षण चल रहा है । अभी तक लगभग 6.75 लाख सफाई कर्मचारियों की पहचान की गई है । राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1992-93 के दौरान 27,618 सफाई कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने व 65,140 का पुर्नवास करने के लक्ष्य के मुकाबले 15,592 को प्रशिक्षित व 19,189 का पुनर्वास किया गया है । इस प्रकार राज्यों द्वारा वांछित स्तर तक योजना का कार्यान्वयन नहीं किया गया है ।

सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों की मुक्ति व पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता राज्य सरकारों की आवश्यकताओं के आधार पर प्रदान की जाती है । विभिन्न राज्य सरकारो/संघ राज्य क्षेत्रों को 1991-92 के दौरान 50.50 करोड़ रुपये तथा 1992-93 के दौरान 60.73 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त की गई थी । राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में है ।